CEASI MILES

19th August 2025

HINDI

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI
CENTRES OF EXCELLENCE FOR AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

CEFMI
Centre of Excellence for Farm Mechanization Skills in India

CEHSI
Centre of Excellence for Horticulture Skills in India

www.ceasi.in

हमारे बारे में

हम कौन हैं:

"सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)" एक स्वायत्त संस्था है, जो "एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)" के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशलयुक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- 15+ राज्य
- 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

लघु कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए टीएनएयू ने उद्योग के साथ साझेदारी की

तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टीएनएयू) ने वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि तमिलनाडु में लघु कृषि मशीनीकरण पर जागरूकता, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके।

यह सहयोग लघु कृषि यंत्रों पर अग्रणी शोध, छात्रों का आधुनिक कृषि तकनीकों में प्रशिक्षण और किसानों व विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रमों पर केंद्रित है। इसमें स्थानीय परिस्थितियों में मशीनरी का परीक्षण और मूल्यांकन, टीएनएयू छात्रों के लिए परियोजना अवसर और इंटर्नशिप प्रदान करना तथा तकनीकी प्रगति पर भविष्य के अनुसंधान को समर्थन देना शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि यह साझेदारी अकादमिक अनुसंधान और व्यावहारिक कृषि समाधान के बीच की खाई को पाटने का उद्देश्य रखती है, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। इस पहल से छात्रों को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा और किसानों को प्रभावी व किफायती मशीनीकरण तकनीकों तक पहुँच होगी।

यह कार्यक्रम नवाचार, शिक्षा और फील्ड-रेडी अनुप्रयोगों को मजबूत करने की उम्मीद करता है, जिससे सतत खाद्य उत्पादन और कृषि क्षेत्र में कौशल विकास को समर्थन मिलेगा।

किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार ने बड़े सुधारों की घोषणा की

भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और सतत कृषि विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक समेकित रणनीति अपनाई है। प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाना, खेती की लागत घटाना, लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना, विविधीकरण को बढ़ावा देना, फसलोत्तर मूल्य संवर्धन को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के अनुरूप खेती को बढ़ावा देना शामिल है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 2013–14 में ₹21,933.50 करोड़ से बढ़कर 2025–26 में ₹1,27,290.16 करोड़ हो गया है। कृषि राज्य का विषय होने के बावजूद, केंद्र सरकार नीतियों, योजनाओं और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों का समर्थन करती है। लागू प्रमुख योजनाओं में पीएम-किसान, पीएम फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना निधि, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कृषि मशीनीकरण उप-मिशन, पीएम-आशा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, नमो ड्रोन दीदी, तथा विविधीकरण, मृदा स्वास्थ्य, बागवानी, तिलहन और डिजिटल कृषि संबंधी पहलें शामिल हैं।

ये सुधार उत्पादकता बढ़ाने, अवसर पैदा करने और किसानों की आजीविका को मजबूत करने की उम्मीद करते हैं।

जम्मू-कश्मीर में समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा

श्रीनगर, 12 अगस्त: जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव ने समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा की, जो पूरे केंद्रशासित प्रदेश में 29 योजनाओं को कवर करता है। समीक्षा में जिला-वार प्रगति, किसान भागीदारी और वार्षिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विभागों और उपायुक्तों को गति बनाए रखने और देरी से बचने के लिए कहा गया, जबकि एचएडीपी प्रबंधन को समय पर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों के साथ निकट समन्वय बनाए रखने के लिए कहा गया।

पाँच वर्षीय एचएडीपी कृषि और बागवानी को टिकाऊ और लाभकारी क्षेत्रों में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र की कृषि-बागवानी क्षमता का उपयोग होगा।

जनवरी 2025 से किसानों का पंजीकरण 35% बढ़कर 3.01 लाख हो गया है, जबकि कुल आवेदन 4.92 लाख तक पहुँच गए हैं, जो 33% की वृद्धि है। इनमें से 3.48 लाख आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जो 24% की वृद्धि दर्शाता है। कृषि मशीनीकरण और ऑटोमेशन योजना को सबसे अधिक प्रतिक्रिया मिली है (74,448 स्वीकृति), इसके बाद चारा संसाधन विकास (36,129) और सब्ज़ी/विशिष्ट सब्ज़ी प्रोत्साहन (33,202) रहे।

तमिलनाडु ने 2025 के लिए ₹500 करोड़ कृषि सहायता योजना शुरू की

तमिलनाडु ने 2025 के लिए ₹500 करोड़ की कृषि सहायता योजना की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना, आधुनिक प्रथाओं को अपनाना और जलवायु व बाज़ार की चुनौतियों के प्रति लचीलापन विकसित करना है। यह पहल राज्यभर में लाखों किसानों को लाभ पहुँचाने की उम्मीद है, जिसमें पारंपरिक फसलें और उभरते कृषि क्षेत्र दोनों शामिल हैं।

योजना का ध्यान सब्सिडी दरों पर गुणवत्तापूर्ण बीज और इनपुट उपलब्ध कराने, सूक्ष्म सिंचाई और नहर मरम्मत के माध्यम से सिंचाई का विस्तार करने, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और ड्रोन पर सब्सिडी देकर मशीनीकरण को बढ़ावा देने और किसान मंडियों, भंडारण सुविधाओं और ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से विपणन को सुधारने पर है। सतत प्रथाओं और जलवायु अनुकूलन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

मुख्य लक्ष्य 20 लाख किसानों को सब्सिडी वाले बीज वितरित करना, 1.5 लाख हेक्टेयर को माइक्रो-इरिगेशन के अंतर्गत लाना, 10,000 आधुनिक कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराना और 50 नए किसान उत्पादक संगठन स्थापित करना है।

पूरी तरह से राज्य बजट से वित्तपोषित यह योजना किसानों की भागीदारी पर ज़ोर देती है, जिससे व्यावहारिक और व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली हस्तक्षेप सुनिश्चित हो सके।

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) को खट्टे फलों में जैव-नियंत्रण बढ़ाने के लिए 24 लाख रुपये का MIDH प्रोजेक्ट मिला

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) को बागवानी के एकीकृत विकास मिशन (MIDH) के तहत 24 लाख रुपये की परियोजना मिली है, जिसका उद्देश्य खट्टे फलों में रोग प्रबंधन के लिए जैव-नियंत्रण को बढ़ावा देना है। यह तीन वर्षीय परियोजना, पौध रोग विज्ञान विभाग को प्रदान की गई है, जिसमें Trichoderma asperellum नामक जैव-नियंत्रण एजेंट का उपयोग करके साइट्रस में फुट रॉट और गम्मोसिस रोग के प्रबंधन के लिए अग्रिम पंक्ति के प्रदर्शन किए जाएंगे। इस प्रयास से खट्टे फलों के किसानों को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल रोग प्रबंधन समाधान मिलने की उम्मीद है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होगी।

PAU के कुलपति डॉ. सतबीर सिंह गोसल ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह परियोजना विश्वविद्यालय की शोध उत्कृष्टता और पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ कृषि प्रथाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल बागवानी नवाचार में PAU के योगदान का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है।

हरियाणा ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 'भावांतर भरपाई योजना' में शहद को शामिल किया

किसानों और मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि अब शहद को भी 'भावांतर भरपाई योजना' (BBY) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा, जैसे बागवानी फसलों को किया गया है। इस कदम का उद्देश्य शहद उत्पादकों को उचित मूल्य सुनिश्चित करना और पूरे राज्य में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को लाभदायक उद्यम के रूप में बढ़ावा देना है।

रामनगर स्थित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र (IBDC) में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के दौरान, मुख्यमंत्री सैनी ने यह भी घोषणा की कि केंद्र में शहद बिक्री और भंडारण सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसमें गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था होगी। 20 करोड़ रुपये की लागत से एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भी इस पहल को और मजबूती देगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन न केवल ग्रामीण आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि परागण के माध्यम से फसल उत्पादकता को भी बढ़ाता है। उन्होंने युवाओं और महिलाओं से अपने स्वयं के शहद ब्रांड शुरू करने का आह्वान किया। उपकरणों पर 85% तक की सब्सिडी और "स्वीट रिवोल्यूशन" की दृष्टि के साथ, हरियाणा खुद को एपीकल्चर (मधुमक्खी पालन) के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

गोवा हॉर्टिकल्चरल कॉरपोरेशन गणेश चतुर्थी पर सब्सिडी दरों पर बेचेगा 25,000 नारियल

त्योहारी खर्च को कम करने के लिए, गोवा स्टेट हॉर्टिकल्चरल कॉरपोरेशन लिमिटेड (GSHCL) ने शुक्रवार से 25,000 नारियल सब्सिडी दर ₹40 प्रति नग पर बेचने की घोषणा की है। ये नारियल राज्यभर के 1,250 हॉर्टिकल्चरल आउटलेट्स के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे।

GSHCL के चेयरमैन प्रेमेंद्र शेट ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य कीमतों को स्थिर करना और गणेश चतुर्थी के दौरान, जब नारियल की मांग चरम पर होती है, उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है। राज्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निगम कर्नाटक के शिवमोग्गा से 15 टन नारियल खरीद रहा है।

प्रबंध निदेशक चंद्रहास देसाई ने कहा कि निगम त्यौहार के ग्यारहवें दिन तक हर हफ्ते कम से कम 25,000 नारियल की खरीद जारी रखेगा।

वर्तमान में छोटे नारियल ₹37–40 और बड़े नारियल ₹58–60 में बिक रहे हैं, ऐसे में सब्सिडी दर से घरों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यह कदम त्योहारों के दौरान आवश्यक वस्तुएं उचित दाम पर उपलब्ध कराने में GSHCL की भूमिका को दर्शाता है।

अरुणाचल की महिला एसएचजी ने केले की खेती को बनाया सशक्तिकरण का मॉडल

चांगलांग ज़िले के जुंगमाइसंग गाँव की एक महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत सफलता की नई कहानी लिखी है। लोंगरोk एसएचजी ने दो वर्ष पूर्व राज्य की बागवानी योजना के तहत केले की खेती शुरू की थी, जो अब एक सफल प्लांटेशन में बदल चुकी है और नियमित आय के साथ आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान कर रही है।

केले की बिक्री से हुई आय ने समूह की कोष निधि को मजबूत किया है, जिससे लंबे समय तक टिकाऊपन और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हुआ है। हाल ही में जब स्थानीय अधिकारियों ने इस प्लांटेशन का दौरा किया, तो उन्होंने इसे महिला सामूहिक प्रयास और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का बेहतरीन उदाहरण बताया।

कृषि एवं बागवानी विभाग, मंत्री गेब्रियल डी. वांगसू के नेतृत्व में, अरुणाचल प्रदेश भर में ऐसे किसान कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे हजारों किसानों को लाभ हुआ है।

लोंगरोk एसएचजी की यात्रा इस बात को दर्शाती है कि महिला-नेतृत्व वाली खेती न केवल ग्रामीण समृद्धि को गति दे सकती है बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में समुदायों को प्रेरित भी कर सकती है।

राजस्थान का पहला सेक्स-सॉर्टेड सीमेन लैब बस्सी में शुरू

जयपुर के पास बस्सी में मवेशियों के लिए अत्याधुनिक सेक्स-सॉर्टेड सीमेन प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यह सुविधा पशुधन प्रजनन और दुग्ध उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह लैब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF), राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (RLDB) और एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDDB Dairy Services) के सहयोग से स्थापित की गई है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख खुराक होगी, जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च गुणवत्ता और किफायती सीमेन उपलब्ध कराना है।

सेक्स-सॉर्टेड सीमेन की कीमत ₹239 प्रति खुराक, देशी नस्ल के सीमेन की ₹22 प्रति खुराक और आयातित नस्ल के सीमेन की ₹30 प्रति खुराक तय की गई है। अतिरिक्त खुराक बाजार दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी।

उत्पादन के अलावा, यह प्रयोगशाला एक प्रशिक्षण और संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी, जिससे डेयरी किसानों को ज्ञान, जागरूकता और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। यह पहल दूध उत्पादन बढ़ाने, पशुधन की नस्ल सुधारने और दुग्ध क्षेत्र में सतत विकास में योगदान करने की उम्मीद है।

दिल्ली मिल्क स्कीम ने नए डेयरी उत्पाद लॉन्च किए और बूथ आवंटन वितरित किए

दिल्ली मिल्क स्कीम (DMS) ने गाय के दूध और सह-ब्रांडेड डेयरी उत्पादों की एक नई श्रृंखला पेश की है, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करना, उपभोक्ता विश्वास को बढ़ाना और पशुपालक किसानों को सशक्त बनाना है। यह लॉन्च 13 अगस्त 2025 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा, नई दिल्ली में किया गया।

उत्पाद लॉन्च के साथ-साथ, डीएमएस ने 22 चयनित आवेदकों को बूथ आवंटन पत्र भी वितरित किए। यह पहल रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ ग्रामीण–शहरी डेयरी संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है। अपने उत्पाद पोर्टफोलियो का विस्तार करके, डीएमएस का लक्ष्य अधिक उपभोक्ताओं तक पहुँचना और दिल्ली व एनसीआर में सुरक्षित एवं पौष्टिक दूध और डेयरी उत्पादों की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हरियाणा मिल्क फेडरेशन के साथ साझेदारी में सह-ब्रांडेड उत्पादों की शुरुआत डेयरी क्षेत्र में सहयोगात्मक वृद्धि की दिशा में एक और कदम है। उत्पाद विविधीकरण और उपभोक्ता जुड़ाव पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करते हुए, डीएमएस खुद को एक विश्वसनीय ब्रांड के रूप में स्थापित कर रहा है और व्यापक डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान दे रहा है।

छत्तीसगढ़ में पशुधन सुरक्षा और ग्रामीण विकास के लिए गौधाम योजना शुरू होगी

छत्तीसगढ़ सरकार गौधाम योजना लागू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य पशुधन की सुरक्षा को मजबूत करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत मवेशियों के लिए सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराया जाएगा, विशेषकर उन पशुओं के लिए जो अवैध परिवहन से बचाए गए हों या आवारा हों। इसके साथ ही यह पहल गाँवों में नए आय अवसर भी उत्पन्न करेगी।

कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गौधाम में लगभग 200 मवेशियों को रखने की सुविधा होगी, जिसमें सुरक्षित बाड़बंदी, शेड, पानी और बिजली की व्यवस्था शामिल होगी। गोपालकों को ₹10,916 मासिक मानदेय और पशु परिचारकों को ₹13,126 मासिक मानदेय मिलेगा, साथ ही चारे के लिए निश्चित दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा। उत्कृष्ट गौधामों को प्रति पशु प्रोत्साहन भुगतान मिलेगा, जो पहले वर्ष में ₹10 से शुरू होकर चौथे वर्ष तक ₹35 तक होगा।

योजना के अंतर्गत जैविक खेती और चारा विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए प्रति एकड़ ₹47,000 तथा पाँच एकड़ के लिए ₹2.85 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजीकृत समितियों या पात्र स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित यह योजना नस्ल सुधार, पशु कल्याण और सतत ग्रामीण रोजगार को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती है।

जम्मू-कश्मीर के डेयरी क्षेत्र में बदलाव के लिए ₹1,433 करोड़ का निवेश

जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू-कश्मीर डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (JKDPIDS) की शुरुआत ₹1,433 करोड़ के निवेश के साथ की है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र के डेयरी क्षेत्र का आधुनिकीकरण करना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना है।

योजना के तहत अगले सात वर्षों में संगठित दूध प्रसंस्करण को वर्तमान 4% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सीधे तौर पर 5 लाख से अधिक डेयरी किसानों को लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के प्रबंधन में यह पहल 18 जिलों में 10 स्वचालित दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करेगी, दूध संग्रहण प्रणाली को मजबूत करेगी और गुणवत्ता व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 100 दूध परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी।

किसानों को सशक्त बनाने के लिए योजना के अंतर्गत 10,000 किसान-स्वामित्व वाली डेयरी समितियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्स्ड सीमेन उत्पादन और चारा विकास के समझौते भी शामिल होंगे, जिससे उत्पादकता बढ़ सके। वित्तीय प्रवाह को सुगम बनाने के लिए नाबार्ड की मदद ली जाएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे के विकास के साथ रोजगार सृजन, सहकारी समितियों के कारोबार में वृद्धि और स्वच्छ, निर्यात-योग्य दूध की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। यह पहल जम्मू-कश्मीर में सतत ग्रामीण विकास और किसान समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत में 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन, उत्तर प्रदेश शीर्ष पर

वित्त वर्ष 2023–24 में भारत का कुल दूध उत्पादन 239.30 मिलियन टन तक पहुँच गया है, जिससे देश ने विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स 2024 के अनुसार, इसमें से 1,27,105.15 हजार टन (53.12%) योगदान गायों का और 1,04,388.29 हजार टन (43.62%) योगदान भैंसों का है।

उत्तर प्रदेश 13.11 मिलियन टन गाय का दूध और 24.35 मिलियन टन भैंस का दूध उत्पादन कर देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य बना हुआ है। इसके बाद राजस्थान 14.81 मिलियन टन गाय का दूध और 16.79 मिलियन टन भैंस का दूध उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख राज्यों में गुजरात, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र शामिल हैं।

दक्षिण भारत में अलग पैटर्न देखने को मिलता है, जहाँ कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में गाय के दूध का उत्पादन भैंस के दूध की तुलना में काफी अधिक है। वहीं छोटे राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र सीमित योगदान करते हैं, जहाँ भैंस के दूध का उत्पादन बहुत कम है।

भैंस का दूध, जिसमें वसा की मात्रा अधिक होती है, उत्तर और पश्चिम भारत में घी, पनीर और खोया जैसे उत्पाद बनाने में विशेष महत्व रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी प्रगति और क्षेत्र-विशिष्ट रणनीतियों के साथ भारत का डेयरी क्षेत्र आगे भी लगातार बढ़ता रहेगा, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी।

केंद्रीय मंत्री ने असम कृषि विश्वविद्यालय को 78वें स्थापना दिवस पर सराहा

विदेश राज्य मंत्री एवं वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्घेरिटा ने शनिवार को असम कृषि विश्वविद्यालय (AAU) के 78वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्य के कृषि विकास में विश्वविद्यालय की परिवर्तनकारी भूमिका की सराहना की।

मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए, मार्घेरिटा ने असम और पूर्वोत्तर के कृषि परिदृश्य को नया रूप देने में AAU के अपार योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का पहला कृषि विश्वविद्यालय होने के नाते, AAU ने किसानों को सशक्त किया है, कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा दिया है और नवाचार, शिक्षा एवं अनुसंधान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया है।

उन्होंने कहा, "असम के कृषि क्षेत्र के विकास में AAU का योगदान अपार है। इसे प्रयोगशाला अनुसंधान और खेतों में उसके उपयोग के बीच की खाई को पाटना जारी रखना चाहिए। असम के कृषि का भविष्य टिकाऊ प्रथाओं और तकनीकी अपनाने पर निर्भर करता है और यह विश्वविद्यालय उस मिशन के अग्रणी मोर्चे पर है।"

प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को ₹2,481 करोड़ की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) की शुरुआत करेंगे। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम ₹2,481 करोड़ का है, जिसका उद्देश्य 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और 1 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना है।

नीति आयोग द्वारा परिकल्पित और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू इस मिशन के लिए केंद्र (₹1,584 करोड़) और राज्य सरकारें (₹897 करोड़) संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराएंगी। इस योजना के लिए किसानों का पंजीकरण पहले से जारी है।

दो वर्ष का यह कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, लागत घटाने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन पर केंद्रित है। इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना में 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर, सरल प्रमाणन, एकीकृत ब्रांडिंग और रियल-टाइम जियो-टैग्ड मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।

स्वतंत्रता दिवस: केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हितों की पुनः पुष्टि की, रबी फसल मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक करेंगे गाँवों का दौरा

नई दिल्ली, 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस समारोह में पूसा कैंपस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया कि उनके हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने घोषणा की कि 3 से 18 अक्टूबर तक कृषि वैज्ञानिक गाँवों का दौरा करेंगे और रबी फसल में सुधार हेतु मार्गदर्शन देंगे।

मंत्री ने किसानों से स्वदेशी आंदोलन अपनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि ऐसे विकल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को सभी नीतिगत निर्णयों में संरक्षण मिलेगा, जिसमें व्यापार समझौते भी शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सरकारी जवाबदेही पर बल दिया और कहा कि जिन कंपनियों के कीटनाशकों से फसलें प्रभावित हुईं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने दोहराया कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए निरंतर समर्थन दिया जाएगा।

कार्यक्रम में राज्य मंत्री, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और आईसीएआर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

नुज़ीवेदु सीड्स लिमिटेड प्रोजेक्ट टीम के लिए सीईएएसआई ने सड़क सुरक्षा कौशल पर कार्यशाला आयोजित की

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI) ने नुज़ीवेदु सीड्स लिमिटेड (NSL) की प्रोजेक्ट टीम के लिए सड़क सुरक्षा कौशल पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन करनाल, हरियाणा में किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य फील्ड टीमों की जागरूकता और तत्परता को बढ़ाना था ताकि वे सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित कर सकें, विशेषकर उन पेशेवरों के लिए जो नियमित रूप से किसानों तक पहुँचने और ग्रामीण विस्तार गतिविधियों में संलग्न रहते हैं।

कार्यशाला की विशेष आकर्षण वराहा द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सत्र रहा, जिसमें किसानों को कार्बन क्रेडिट पंजीकरण से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र में प्रतिभागियों को कार्बन बाजारों के महत्व और उन भूमिकाओं से अवगत कराया गया जो किसान जलवायु-स्मार्ट प्रथाएँ अपनाकर निभा सकते हैं। इससे न केवल पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी बल्कि किसानों के लिए अतिरिक्त आय का मार्ग भी खुलेगा।

यह कार्यशाला न केवल प्रोजेक्ट टीम की क्षमताओं को मजबूत करने में सहायक रही, बल्कि इसने NSL प्रोजेक्ट के FY 2025-26 की औपचारिक शुरुआत भी की। इसने सुरक्षित कार्यप्रणाली, किसान सशक्तिकरण और स्थायी कृषि पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने की नींव रखी।

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA

(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45, Gurugram, Haryana-122009

+91 74287 06078

info@cedsi.in

www.ceasi.in

@ceasi_india